

66

संख्या - 1151 / V-2011-39(आ0) / 2011

प्रेषक,

पी0सी0 शर्मा,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

उपाध्यक्ष,
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण
देहरादून।

आवास अनुभाग-2

देहरादून, दिनांक 07 जुलाई, 2011

विषय : चकराता रोड़ चौड़ीकरण के फलस्वरूप विस्थापितों हेतु आई0एस0बी0टी0, देहरादून में 02 कमरों के 96 आवासीय भवनों के निर्माण कार्य की प्रशासकीय तथा व्यय की स्वीकृति।

महोदय,

कृपया अपने पत्र संख्या-131/लेखा/2011 दिनांक 18 अप्रैल, 2011 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस सम्बन्ध में उल्लेख कराना है कि वित्तीय वर्ष-2010-2011 में चकराता रोड़ चौड़ीकरण करने की योजना के दृष्टिगत लोक निर्माण विभाग निरीक्षण भवन परिसर घंटाघर, देहरादून में व्यवसायिक भवन एवं वैकल्पिक व्यवस्था के अन्तर्गत दो कमरों के 96 आवासों के निर्माण कार्य हेतु शासनादेश सं0-275/V/2010-126(आ0)/10 दिनांक 03-2-2011 के द्वारा उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लि0 द्वारा प्रेषित प्रथम चरण के कार्यों हेतु अनुमानित लागत रू0 56.86 लाख के आगणन के सापेक्ष तकनीकी परीक्षणोपरान्त संस्तुत लागत रू0 54.61 लाख (रू0 चौवन लाख इकसठ हजार मात्र) के आगणन की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी थी, जिसमें से व्यवसायिक भवनों के निर्माण हेतु प्रथम चरण के कार्यों हेतु रू0 46.40 लाख एवं दो कमरों के 96 आवासों का निर्माण हेतु 8.61 लाख की धनराशि सम्मिलित थी।

3- इस क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चकराता रोड़ चौड़ीकरण के फलस्वरूप विस्थापितों हेतु आई0एस0बी0टी0, देहरादून में 02 कमरों के 96 आवासीय भवनों के निर्माण कार्य हेतु प्रस्तुत आगणन रू0 540.85 लाख के सापेक्ष टी0ए0सी0 वित्त एवं व्यय वित्त समिति द्वारा आंकलित कुल 519.33 लाख (रुपये पांच करोड़

72/11

उन्नीस लाख तैंतीस हजार मात्र) की लागत की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए महामहिम राज्यपाल इस योजना के प्रारम्भिक चरण हेतु अवमुक्त की गई धनराशि रु0 8.61 लाख की धनराशि को कम करते हुए शेष धनराशि रु0 510.72 लाख (रुपये पांच करोड़ दस लाख बहत्तर हजार मात्र) की धनराशि को वर्तमान वित्तीय वर्ष 2011-12 में निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन व्यय हेतु अवमुक्त करने की भी श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

- (1) व्यय वित्त समिति का अनुमोदन मात्र आवासीय भवनों के निर्माण तक सीमित है लेकिन चकराता रोड के चौड़ीकरण के फलस्वरूप विस्थापित निवासियों को आवास आवंटित करने का प्रकरण **compensation** से सम्बन्धित एक महत्वपूर्ण नीतिगत विषय होने के कारण आवास विभाग द्वारा इस पर पृथक से मा0 मंत्रिपरिषद से निर्णय कराना सुनिश्चित कराया जाये।
- (2) चकराता रोड के प्रस्तावित निवासियों जिन्हें विस्थापन के फलस्वरूप आवास आवंटित किये जाने प्रस्तावित हैं, उनसे पूर्व सहमति प्राप्त कर ली जाये।
- (3) योजना प्रस्ताव में चिन्हित भूमि को एम0डी0डी0ए0 का अंशदान माना जायेगा तथा राज्य सरकार का अंशदान योजना प्रस्ताव के आवास निर्माण तक सीमित रहेगा।
- (4) योजना प्रस्ताव पर सैद्धान्तिक सहमति इस शर्त के अनुसार प्रदान की जाती है कि नियोजन विभाग के तकनीकी अभियंताओं की टीम निर्माण स्थल का निरीक्षण करते हुए detailed estimate का पुनः परीक्षण कर अपनी संस्तुति प्रस्तुत करेगी।
- (5) Third party inspection/Monitoring की व्यवस्था नियोजन विभाग के माध्यम से सुनिश्चित की जाये।
- (6) यह भी सुनिश्चित करें कि उपर्युक्त स्वीकृति से अधिक व्यय किसी भी दशा में न किया जाये तथा व्यय उसी मद में किया जाये जिसके लिये धनराशि स्वीकृत की जा रही है।
- (7) व्यय से पूर्व बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों एवं तदविषयक निर्गत अन्य आदेशों का अनुपालन किया जायेगा।
- (8) कार्य करने से पूर्व मदवार विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियंता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों के आधार पर तथा जो दरें शेड्यूल ऑफ रेट्स में स्वीकृत नहीं है, अथवा बाजार भाव से ली गयी हों, की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियंता/सक्षम अधिकारी से अनुमोदन कराना आवश्यक होगा।

- (9) कार्य पर उतना ही व्यय किया जाए जितनी धनराशि स्वीकृत की गयी है स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाये।
- (10) कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि के मददेनगर राखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों एवं विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य को सम्पादित किया जाना सुनिश्चित किया जाये।
- (11) मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-2047/XVI-219(2006) दिनांक 30-5-2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कड़ाई से पालन किया जाये।
- (12) यदि विभिन्न मदों हेतु स्वीकृत धनराशि अवशेष रहती है तो उक्त धनराशि द्वितीय चरण के आगणन में समायोजित की जाये।
- (13) कार्य प्रारम्भकराने से पूर्व उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
- (14) स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक 31-3-2012 तक पूर्ण उपयोग कर स्वीकृत धनराशि की कार्यबार वित्तीय एवं भौतिक प्रगति का विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।
- (15) कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता हेतु निर्माण एजेन्सी पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगी।

4- स्वीकृत धनराशि का आहरण 3 समान किशतों में उपाध्यक्ष, मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण द्वारा बिल बनवाकर जिलाधिकारी, देहरादून के प्रतिहस्ताक्षर से किया जायेगा तथा निर्माण एजेन्सी के सक्षम प्राधिकारी को उपलब्ध कराया जायेगा। पूर्व किशत का पूर्ण उपयोग करके ही आगामी किशत का आहरण कोषागार से किया जायेगा।

5- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष-2011-2012 में अनुदान संख्या-13 के अन्तर्गत "लेखाशीर्षक 2217-शहरी विकास-03-छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास-आयोजनेत्तर-191-स्थानीय निकायों, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरणों, नगर सुधार बोर्डों को सहायता-03 नगरों का समेकित विकास-0312-भूमि अधिग्रहण एवं पुनर्वासन-24 वृहत निर्माण" के नामें डाला जायेगा।



6- यह आदेश वित्त अनुभाग-2 के अशा0 संख्या-40/xxvii(2)/2011, दिनांक 06 जुलाई, 2011 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किए जा रहे हैं ।

भवदीय,

(पी0सी0 शर्मा)
प्रमुख सचिव ।

संख्या-1151(17)/V/आ0-2-2011-तददिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- (1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उत्तराखण्ड, माजरा, देहरादून ।
- (2) मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून ।
- (3) सचिव, मुख्यमंत्री को मा0 मुख्यमंत्री जी के अवलोकनार्थ ।
- (4) जिलाधिकारी, देहरादून ।
- (5) परियोजना प्रबन्धक, उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड, ई-34 नेहरु कालोनी, देहरादून, उत्तराखण्ड ।
- (6) मुख्य कोषाधिकारी, देहरादून ।
- (7) वित्त अनुभाग-1, उत्तराखण्ड शासन ।
- (8) नियोजन अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन ।
- (9) निदेशक, एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड, देहरादून ।
- (10) गार्ड बुक ।

आज्ञा से,

(गरिमा सैकली)
उप सचिव